महत्वपूर्ण एवं खास

पुलिस आंदोलन में शामिल होने वालों पर होगी सख्त कार्रवाही

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश में पुलिस आंदोलन को लेकर डीजीपी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी पुलिस वाला इस प्रोटेस्ट में शामिल होता है या सपोर्ट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं ये भी देखा जाएगा कि किसके परिजन आंदोलन में शामिल हैं इसके बाद परिजनों और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम पुलिस मुख्यालय में एक बैठक में डीजीपी ने विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर कोई भी पुलिस वाला इस प्रोटेस्ट में शामिल होता है या सपोर्ट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि इस बात पुष्ट नहीं हो सकी है।

थाना घेराव के दौरान लाठी चार्ज में विधायक सहित कार्यकर्ता हुए घायल

महासमुंद (आरएनएस)। मिनी स्टेडियम में बाल बैडमिंटन के कोच व स्थानीय लड़कों के साथ हुई मारपीट में महासमुंद निर्दलीय विधायक विमल चोपड़ा ने थाने का घेराव अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर दिया। पुलिस वालों ने विमल चोपड़ा व कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा जिसके कारण विमल चोपड़ा को गंभीर चोटें आई है उन्हें नजदीकी चिकित्सा केंद्र में प्रारंभिक चिकित्सा के लिए भर्ती किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार निर्दलीय विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा और उनके समर्थकों पर बर्बारता पूर्वक लाठी चार्ज किया है। इस लाठी चार्ज के दौरान विधायक के सिर पर गंभीर चोट आई है। कई कार्यकर्ता के हाथ पैर पर गंभीर चोट आई है. जिससे वो गंभीर रुप घायल हो गए है. पूरी तरह से लहूलुहान हो गए है. जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बॉल बैडमिंटन के कोच व स्थानीय लड़कों के साथ हुए मारपीट मामले में विधायक ने अपने सैकडों समर्थकों के साथ कोतवाली थाने का घेराव कर दिया था। जिसको लेकर पुलिस व विधायक समर्थकों के बीच विवाद काफी बढ़ गया। वहीं पुलिस ने बलपूर्वक विधायक समर्थकों को थाने से खदेड़-खदेड़ कर बेरहमी से पिटाई की है। जिससे विधायक और उनके समर्थक गंभीर रूप से घायल हो गए है। पुलिस दोनों पक्ष के खिलाफ कांउटर रिपोर्ट लिख रही है।

12 जून के बाद अच्छी वर्षा की भविष्यवाणी ने अंचल के किसानों को छला

जगदलपुर (आरएनएस)। बस्तर में मानसून का आगमन वैसे हर वर्ष 20-22 जून के बाद ही होता है और जुलाई माह में यह सक्रिय होकर पूरे बस्तर में वर्षा करता है। लेकिन इस वर्ष दक्षिणी पश्चिमी मानसून के इस बार 12 जून को बस्तर पहुंचकर बस्तर में अच्छी वर्षा की संभावना मौसम विभाग ने अपने मौसम पूर्वानुमान में देकर बस्तर के किसानों को एक प्रकार से छल दिया और इसके कारण अंचल के हजारों किसान बुवाई काम कर आज पछता रहे हैं। किसानों के खेतों में हल्की नमी से डाले गए बीज लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से अंकुरित नहीं हो पाए और उनके डाले गये बीज सूखकर नष्ट हो रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि गत 9 जून व 12 जून को अंचल में हुई थोड़ी वर्षा के बाद अभी तक एक बार भी यहां किसी भी हिस्से में तगड़ी बारिश नहीं हुई। वहीं 10 दिनों से मानसून पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक इसके सक्रिय होने की कोई संभावना नहीं है। इसकी वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात या कम दबाव वाला कोई सिस्टम नहीं बना है। जिसके कारण वर्षा की फिलहाल संभावना नहीं है और आने वाले कुछ दिन गर्मी के ही रह सकते हैं। इस प्रकार मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान से बस्तर के लोगों सहित हजारों किसानों को छला है। अभी भी मौसम विभाग के सूत्र बताते हैं कि फिलहाल मानसून निष्क्रिय हो गया है। उम्मीद है कि 23-24 जून तक कोई सिस्टम बनेगा, जिससे तेज बारिश होगी। बीच बीच में स्थानीय प्रभाव से बस्तर में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है।

सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें, अधिकारी-कर्मचारी भी हड़ताल की राह पर

शासकीय अधिकारी-कर्मचारी 27 को करेंगे सांकेतिक हड़ताल

रायपुर (आरएनएस)। शिक्षाकर्मियों के लंबे आंदोलन के बाद अब जहां पुलिस परिजनों द्वारा 25 जून को राजधानी में विशाल धरना-प्रदर्शन का हल्ला मचा हुआ है तो वहीं अब छत्तीसगढ़ के शासकीय विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भी 27 जून को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले होने वाले इस हड़ताल के पीछे कर्मचारियों का तर्क है कि भाजपा सरकार ने घोषणा पत्र में किए गए अपने वादे भूला दिए हैं और वायदे को निभाने में भी सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। फेडरेशन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 09 मई को अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव से चर्चा की थी। इसके साथ ही घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया था। लेकिन चर्चा और ज्ञापन सौंपे जाने के बाद भी सरकार द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है।

डीएमएफ की राशि का विकास कार्यों में उपयोग करने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल

रायपुर (आरएनएस)। मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित बैठक में बताया गया कि जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) की राशि से प्रदेश के खनिज बहुल विभिन्न जिलों में विकास कार्यों के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले नम्बर पर है। छत्तीसगढ़ में इस न्यास में अप्रैल 2018 की स्थिति में 2826 करोड़ रूपए जमा है। डीएमएफ की राज्य स्तरीय समीक्षा समिति की इस बैठक में बताया गया कि न्यास द्वारा 3551 करोड़ रूपए के 30 हजार 24 विकास कार्य स्वीकृत किये गए है। बैठक में जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की गयी। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे विकास कार्य जो प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवश्यक है और जिनके लिए विभागीय बजट की कमी है उनका आंकलन करें और डीएमएफ से इस कार्य की स्वीकृति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि जिला खनिज न्यास निधि के आडीट का कार्य सितम्बर माह तक पूरा कर लिया जाए। उन्होंने डीएमएफ कोष से अधिक से अधिक विकास कार्यों को स्वीकृत किये जाने की बात कही है।

बैठक में खनिज संसाधन विभाग के सचिव सुबोध सिंह ने जानकारी दी कि खदान क्षेत्र के प्रभावित परिवारों और क्षेत्र के विकास के लिए राज्य के प्रत्येक राजस्व जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। जिसके द्वारा खनन से प्राप्त रायल्टी का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए किया जाता है। राज्य में कुल 88 गांव है, जो खनन कार्यों से प्रभावित है। इन्हें आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 से अब तक खनिज न्यास निधि के रूप में 2826 करोड़ रूपए प्राप्त हुए है। जिनमें से 3551 करोड़ रूपए के 30 हजार 24 कार्य स्वीकृत किये गए हैं। स्वीकृत कार्यों में से 1841 करोड़ रूपए के 10 हजार 956 कार्य पूरे किये जा चुके है। शेष कार्य प्रगति पर है। बैठक में बताया गया कि प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए 60 प्रतिशत और अन्य कार्यों के लिए 40 प्रतिशत राशि न्यास निधि से स्वीकृत की जाती है।

आज से 15 दिन रद्द रहेगी टिटिलागढ़, रायगढ़ पैसेंजर, कुछ ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेंगी

बिलासपुर (आरएनएस)। किरोड़ीमल नगर एवं रायगढ़ स्टेशन यार्ड का आधुनिकीकरण एवं चांपा-झारसुगड़ा सेक्शन में तीसरी रेल लाईन को जोड़ने का काम बुधवार से शुरू किया जाएगा। 15 दिन तक चलने वाले इस काम की वजह से बिलासपुर-टिटिलागढ़ और बिलासपुर-रायगढ़ के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 15 दिन रद्द रहेंगी। इस दौरान मुंबई-हावड़ा रूट की कुछ ट्रेनें रायपुर से रूट बदलकर चलेंगी। इसमें सुपर डीलक्स, हापा एक्सप्रेस शामिल हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत किरोड़ीमल नगर एवं रायगढ़ स्टेशन यार्ड का आधुनिकीकरण एवं चांपा-झारसुगड़ा सेक्शन में तीसरी रेल लाईन को जोड़ने के लिए नवीनीकरण का काम किया जाएगा। इस दौरान कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। रेलवे प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है।

अहमदाबाद व साउथ बिहार एक्सप्रेस पैसेंजर बनकर चलेगीः रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते रेलवे प्रशासन ने 19 जून से 3 जुलाई तक 16 दिन ट्रेन क्रमांक 12834 हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस को झारसुगड़ा व रायगढ़ के बीच पैसेंजर बनाकर एवं ट्रेन क्रमांक 13287 दुर्ग-राजेंद्रनगर साउथ बिहार एक्सप्रेस को 23 जून से 4 जुलाई तक चांपा एवं झारसुगड़ा के बीच पैसेंजर बनाकर चलाने का निर्णय लिया है।

तीसरी रेल लाइन परियोजना को यार्ड से जोड़ने का काम किया जाएगा

ये 12 ट्रेनें रद्द रहेंगी

ट्रेन क्रमांक 58214 बिलासपुर-टिटिलागढ़ पैसेंजर बिलासपुर से 20 जून से 4 जुलाई तक 15 दिन। ट्रेन क्रमांक 58213 टिटिलागढ़-बिलासपुर पैसेंजर टिटिलागढ़ से 20 जून से 4 जुलाई तक 15 दिन। ट्रेन क्रमांक 68737 रायगढ़-बिलासपुर मेमू रायगढ़ से 20 जून से 4 जुलाई तक 15 दिन।

ट्रेन क्रमांक 68738 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू बिलासपुर से 20 जून से 4 जुलाई तक 15 दिन। ट्रेन क्रमांक 68735 रायगढ़-बिलासपुर मेमू रायगढ़ से 23 जून से 4 जुलाई तक 12 दिन। ट्रेन क्रमांक 68736 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू बिलासपुर से 22 जून से 3 जुलाई तक 12 दिन।

जम्मू-कश्मीर में मुख्य सचिव बन सकते हैं आईएएस सुब्रमण्यम

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के गृह विभाग में बतौर एसीएस कार्यरत आईएएस अफसर बीवीआर सुब्रमण्यम को जम्मू-कश्मीर भेजा जा रहा है। केन्द्रीय कैबिनेट की हुई बैठक के बाद इस आशय का आदेश जारी कर दिया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 1987 बैच के आईएएस अफसर श्री सुब्रमण्यम को जम्मू-कश्मीर में मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। हालांकि अभी इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया है, लेकिन जानकारों की माने तो उन्हें मुख्य सचिव के रूप में जम्मू-कश्मीर भेजा रहा है। ज्ञात हो कि श्री सुब्रमण्यम मनमोहन सिंह के कार्यकाल में केन्द्र में संयुक्त सचिव का पद संभाल चुके हैं।

रेलवे पुलिस ट्रेनों में सामान चेकिंग के नाम पर कर रही है अतिरिक्त कमाई

रायपुर (आरएनएस)। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेनों में रेलवे पुलिस के जवानों की ड्यूटी रेलवे द्वारा लगाई जाती है ताकि यात्रयों के जान माल की हानि न हो सके। किंतु कुछ रेलवे पुलिस के जवानों द्वारा ट्रेनों में जनरल बोगी में चढ़कर यात्रियों की सामान की जांच के नाम पर वसूली किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला कल रायपुर के प्लेटफार्म नंबर दो पर देखने को मिला। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में मंगलवार शाम को जब रायपुर पहुंची तो सामान के साथ जनरल बोगी में चढ़ रहे दो लड़कों से रेलवे पुलिस के सिपाही ने जनरल डिब्बा उसका सामान चढ़ाकर खुद भी बोगी में सवार हो गया। बोगी में चढ़ते ही सफर कर रहे यात्रियों से गाली गलौज करते हुए टिकिट व सामान की जांच करने की बात करने लगा। एक यात्री से सामान रखने के नाम पर सौ रुपए

लेकर जनरल बोगी से उतरकर दूसरी बोगी में चला गया। यात्रियों से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर से आमगांव तक जाने वाले दो लड़के रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर कृषि से संबंधित केबल वायर का एक छोटा सा कार्टून लेकर ट्रेन में चढ़ रहे थे उसी दौरान रेलवे पुलिस का एक जवान के द्वारा सामान को जनरल बोगी में चढ़वाया व खुद भी एक व्यक्ति के साथ जनरल बोगी में घुस आया।

सिटी एसपी व सब इंस्पेक्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हुई तो विधानसभा में पद से इस्तीफा दे दूंगा-डॉ. विमल चोपड़ा

महासमुंद (आरएनएस)। महासमुंद के निर्दलीय विधायक डा. विमल चोपड़ा व उनके समर्थकों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को विधायक समर्थकों ने महासमुंद बंद का आव्हान किया गया था। हालांकि इस बंद का असर मिला-जुला रहा। इस बंद के दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे घायल विधायक विमल चोपड़ा ने कहा कि इस मामले में वे विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री से फोन पर बातचीत कर घटना की पूरी जानकारी दे चुके है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर दोषी पुलिस अधिकारी उदय किरण और सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर यहां से हटाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वे आगामी विधानसभा सत्र के दौरान अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।

डा. विमल चोपड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जिले में सिटी एसपी उदय किरण अपनी दुर्व्यवहार के कारण पहले से ही चर्चा में है। उन्होंने कहा कि मिनी स्टेडियम के खिलाड़ियों के साथ सब इस्पेक्टर द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के मामले में वे उक्त सब इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर थाना पहुंचे थे।

मुख्यमंत्री ने व्यापारियों-उद्योगों को ई-वे बिल से दी बड़ी राहत

राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारीः अब प्रदेश के भीतर माल परिवहन

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश के व्यापारियों और उद्योगों को ई-वे बिल से एक बड़ी राहत दी है। इस सिलसिले में राज्य शासन द्वारा अधिसूचना यहां जारी कर दी गई। यह अधिसूचना तत्काल प्रभावशील हो गई है। उल्लेखनीय है कि जीएसटी के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर 50 हजार रूपए से ज्यादा के माल परिवहन के लिए ई-वे बिल जनरेट करने का प्रावधान एक जून 2018 से लागू किया गया था।

इसके बाद राज्य के व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से यह अनुरोध किया था कि प्रदेश में व्यापार और उद्योग जगत को राहत देने के लिए ई-वे बिल प्रणाली सिर्फ कुछ वस्तुओं पर ही लागू की जाए और एक जिले के भीतर होने वाले माल परिवहन को इससे छूट दी जाए।

अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस का आयोजन 26 को

रायपुर (आरएनएस)। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस का आयोजन 26 जून को आयोजित किया गया है। इस अवसर पर विभिन्न समाजसेवी संगठनों द्वारा नशे से होने वाली बर्बादी एवं नशे के चलते होने वाली मौतों को रोकने के लिए जनजागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। विभिन्न स्कूल कालेजों आंगनबाड़ी केंद्रों सहित शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर नशे से होने वाली हानियों के पोस्टर चित्र आदि लगाकर स्वंयसेवी कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को नशीले पदार्थों का सेवन रोकने के संदेश लेकर जागरूक किया जाएगा।

फैक्ट्री के आलमारी से नगद 35 हजार पार

रायपुर (आरएनएस)। ग्राम भुरकोनी स्थित सांई वॉटर फैक्ट्री के आलमारी को काटकर अज्ञात चोर 35 हजार रूपए पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर विधानसभा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अंकित अग्रवाल पिता नंदकिशोर अग्रवाल 24 वर्ष केपिटल हाऊस सड्डू का रहने वाला है।

पुलिस कर्मियों की सभी जरूरतों को संवेदनशीलता से पूरा कर रही सरकार : गृहमंत्री पैकरा

कठिन और चुनौतीपूर्ण ड्यूटी को देखते हुए दिया जा रहा एक महीने का अतिरिक्त वेतन

रायपुर (आरएनएस)। गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा है कि राज्य सरकार पुलिस कर्मियों की सभी बुनियादी जरूरतों को संवेदनशीलता और सहृदयता के साथ पूर्ण कर रही है। उन्होंने कहा -मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार नक्सल मोर्चे पर तैनात पुलिस जवानों के साथ-साथ प्रदेश के अन्य जिलों में पदस्थ पुलिस कर्मियों के लिए भी आवश्यक सुविधाओं में वृद्धि कर रही है और उन्हें हर संभव बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं।

श्री पैकरा ने आज यहां इन सुविधाओं का उल्लेख करते हुए यह भी बताया कि राज्य

शासन द्वारा पुलिस कर्मचारियों की लगातार कठिन और चुनौतीपूर्ण ड्यूटी को ध्यान में रखकर उन्हें एक महीने का अतिरिक्त वेतन भी दिया जा रहा है। साथ ही उनके लिए 15 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश का भी प्रावधान किया गया है, जो शासन द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न अवकाशों से अलग है। इसे केवल पुलिस कर्मचारियों को ही दिया जाता है। पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों से भी सुसज्जित किया जा रहा है, ताकि वे अपनी ड्यूटी और भी प्रभावी ढंग से कर सकें।

अब तक पुलिस बल में 48 हजार से ज्यादा भर्तियां

श्री पैकरा ने बताया कि राज्य गठन के बाद प्रदेश में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सहित जिला पुलिस बलों में आरक्षक से लेकर उप पुलिस अधीक्षक संवर्ग तक कुल 48 हजार 477 रिक्त पदों की पूर्ति भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से की गई है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और जिला पुलिस बलों में 1786 और दो हजार 259, इस प्रकार कुल 4045 रिक्त पदों के लिए भर्ती की कार्रवाई की जा रही है। अब तक जिला पुलिस बलों में आरक्षक से लेकर निरीक्षक संवर्ग तक कुल नौ हजार 083 और अन्य संवर्गों में कुल 547 पुलिस कर्मियों को सामान्य क्रम के अनुसार पदोन्नति दी जा चुकी है। इनके अलावा 500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को पुलिस रेग्युलेशन पैरा-70 के प्रावधानों के अनुसार क्रम से पहले पदोन्नत किया गया है।